प्रदूषण फैलाने वालों से वसूली जाए कीमत

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि पर्यावरण मानदंड लागू करें लेकिन लाइसेंस परमिट राज नहीं लौटने पाए

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विकास के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए ऐसे मानदंड बनाए जाने चाहिए, जिनमें प्रदूषण फैलाने वालों से कीमत वसूलने का प्रावधान भी हो। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी चेताया कि मानक लागू करने की आड़ में लाइसेंस राज की वापसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी नीति बनाने पर जोर दिया जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की लोगों की आदतें बदलें।

यहां 'दि एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूटी (टेरी)' द्वारा आयोजित दिल्ली सतत विकास सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इस मौके पर टेरी ने उन्हें जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए नेशनल क्लाईमेट चेंज एक्शन प्लान तैयार करने के लिए सस्टेनेबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। पिछले साल यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र महासचिव बॉन-की मून को दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि

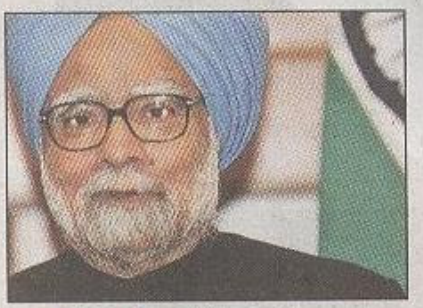

■ मनमोहन सिंह– प्रधानमंत्री

मानक बनाना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें लागू भी करना होगा जो आज सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सिंह ने कहा कि हमें ऐसी ढांचागत नीतियां बनानी होंगी जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की आदतों पर रोक लगा सके।

सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए औद्योगिक देशों को भी अपने उर्त्सजन कटौती की घोषणा करनी चाहिए। ताकि, कोपेनहेगेन जलवायु शिखर सम्मेलन में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। सिंह ने कहा कि भारत ने स्वेच्छा से उर्त्सजन में कटौती की घोषणा करके इस मुद्दे पर वैश्विक जड़ता को तोड़ने की कोशिश की है। इसलिए अब 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक देशों को आगे आना चाहिए। उन्होंने खेद प्रकट किया कि उनकी तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत ग्रीन हाउस गैसों का उर्त्सजन पूरा भी रोक दे तो भी खास अंतर नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसकी हिस्सेदारी सिर्फ चार

सतत विकास सम्मेलन

- ऐसी नीति बने ताकि पर्यावरण क्षति की लोगों की आदतें बदले
- टेरी ने पीएम को ग्रीन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया

खत्म हो विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई : पचौरी

नई दिल्ली। इंटरगर्वमेंटल पैनल ऑन क्लाईमेट चेंज (आईपीसीसी) के चेयरमैन और टेरी के महानिदेशक डॉ. आर.के. पचौरी ने कहा कि 'पर्यावरण बनाम विकास' की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। दिल्ली सतत विकास सम्मेलन (डीएसडीएस) के दौरान पचौरी ने कहा कि विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई विकास परियोजनाओं के रुकने से शुरू हुई है। इसकी वजह यह है कि पहले योजना बनती है फिर पर्यावरण मंजूरी के लिए जाती है। जबकि योजनाकारों को इसका खाका तैयार करते समय ही पर्यावरण से जुड़े मामलों का ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा करें तो यह समस्या खत्म हो सकती है।